भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 951

दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

चारे की कमी

951. श्री सुब्रत पाठक:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री रविन्दर कुशवाहा:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री राम कृपाल यादव:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री रवि किशन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरे चारे, सूखे चारे और मिश्रित चारे की क्रमशः 12-15, 25-26 और 36 प्रतिशत कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हितधारकों के साथ चारा संकट पर समीक्षा बैठक आयोजित की है और यदि हां, तो उक्त बैठक का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चारे की कमी के विभिन्न कारणों का आकलन किया है और यदि हां, तो देश में चारे की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान चारा केंद्रित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) एनडीडीबी द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान कुल कितने एफपीओ स्थापित/गठित किए जाने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा चारा-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क)जी हां। देश में चारे की कमी है। भाकृअनुप-भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईजीएफआरआई), झांसी ने अनुमान लगाया है कि देश में हरे चारे, सूखे चारे और कंस्ट्रेस की क्रमशः 11.24%, 23.4% और 28.9% कमी है।

(ख) देश में चारे की स्थिति की समीक्षा के लिए दिनांक 6.10.2022 को राज्य सरकारों/अन्य पणधारियों के साथ सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। राज्यों ने सूचित किया कि देश में चारा आपूर्ति की इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है लेकिन चारे के मूल्य में वृद्धि की सूचना मिली थी जो मुद्रास्फीति की सामान्य प्रवृत्ति के कारण हो सकता है।

(ग) चारे की खेती के अंतर्गत स्थिर क्षेत्रफल के साथ भूमि उपयोग के पैटर्न में बदलाव, शहरीकरण, चरागाहों की घटती उत्पादकता, वाणिज्य फसलों की ओर भूमि का विपथन, फसल अवशेषों का अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए विपथन, गुणवत्तायुक्त चारा बीजों की उचित मात्रा में अनुपलब्धता, पशुओं की उन्नत उत्पादकता के लिए चारे की बढ़ती मांग देश में चारे की कमी के विभिन्न कारण हैं। केंद्र सरकार देश में आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू कर रही है, जिसमें नकदी फसल के रुप में चारा फसल को बढ़ावा देते हुए उच्च उपज वाली चारा किस्मों के बीज उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे चारा फसलों के तहत और अधिक क्षेत्रफल में विविधता आ पाएगी। इसके अलावा, 50 लाख रु. तक 50% सब्सिडी प्रदान करके चारा ब्लॉकों/हे बेलिंग/साइलेज इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चल रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार, गुणवत्तायुक्त आहार उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए पशु चारा प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित पशु चारा विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2020-21 से पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना का भी कार्यान्वयन कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संरक्षण में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा 20 राज्यों के लिए तैयार किए गए चारा संसाधन योजनाआं को भी कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है।

(घ) और(ड़) 4 नवम्बर, 2022 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने गौण कार्यकलाप (चारा प्लस मॉडल) के रुप में मुख्यतः चारा केंद्रित और पशुपालन कार्यकलापों के लिए 100 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए 10,000 किसान उत्पादकता संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रुप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को अनुमोदित किया है। एनडीडीबी को योजना के दिशानिर्देशों के दायरे में वर्ष 2022-23 के दौरान इन एफपीओ को गठित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

(च) सरकार देश में आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू कर रही है, जिसमें नकदी फसल के रुप में चारा फसल को बढ़ावा देते हुए उच्च उपज वाली चारा किस्मों के बीज उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे चारा फसलों के तहत और अधिक क्षेत्रफल में विविधता आ पाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा 20 राज्यों के लिए तैयार की गई चारा संसाधन योजनाओं को भी इनके कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ साझा किया गया है।

******